भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3628

मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत औद्योगिक नोड

3628. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत विकसित प्रथम औद्योगिक नोड के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नोड के विकास के लिए सरकार द्वारा कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और अब तक स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार के लिए इस नोड के विकास से अनुमानित रोजगार संभावनाएं और आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों/रीजन/नोड्स का विकास करना है।

भारत सरकार ने अगस्त, 2024 में एनआईसीडीपी के तहत, बिहार के गया जिले में विकास के लिए चिह्नित की गई 1,670 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। इसकी कुल परियोजना लागत 1,339 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 807 करोड़ रुपए का है। आईएमसी, गया के संचालन की संभावित समय-सीमा, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों पर निर्भर करती है। अवसंरचना कार्यों को पूरा करने की 36-48 महीने की संभावित समय-सीमा ईपीसी संविदाकार की नियुक्ति की वास्तविक तारीख से शुरू होगी। आईएमसी, गया का कार्य पूरा होने तथा इसके संचालन में आने से रोजगार के लगभग 01 लाख संभावित अवसर उपलब्ध होने का अनुमान है।

*****